बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि०.
"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक, रोड नं० 2 पटना 800001

पत्रांक- 5863 दावा/पटना, दिनांक -21/06/17

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा०प्र०से०,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः- **माननीय सर्वोच्च न्यायालय,** नई दिल्ली द्वारा SLP (Crl.) No. 1779/2016 बिहार राज्य बनाम दिवेश कुमार चौधरी व अन्य सहित कुल 250 SLP (Crl.) में दिनांक **28.02.17** को **पारित आदेश** के आलोक में पाँच जगहों- **पटना, गया, छपरा, दरभंगा एवं पूर्णियाँ** में **विशेष ट्रायल कोर्ट** के गठन हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना से विधि विभाग के माध्यम से अनुरोध करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना से 10% से 20% की राशि जमा कर देने की शर्त पर वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के प्रमादी मिलरों द्वारा अग्रिम जमानत ले लिये जाने के विरूद्ध बिहार राज्य खाद्य निगम/सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुल 250 SLP (Crl.) दायर किया गया। SLP (Crl.) No. 1779/2016 बिहार राज्य बनाम दिवेश कुमार चौधरी व अन्य सहित कुल 250 SLP (Crl.) में एक साथ सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक **28.02.17** को अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश इस प्रकार हैः-

(1) The accused in all the FIR(s), will ensure that bank guarantee, if not furnished, is furnished and if lapsed, is renewed within a period of one month from today failing which the anticipatory bail/bail granted will stand cancelled.
(2) The accused will cooperate with investigation/trial and their failure to appear, when required, will be a ground for cancellation of anticipatory bail/bail. An order of cancellation will be passed by the trial court on being satisfied about such failure.
(3) The investigation will be completed within a period of three months.
(4) All the accused will be tried only at five places viz. Patna, Gaya, Chhapra, Darbhanga and Purnia by officers of the appropriate rank determined by the High Court within one week from today. The High Court may specify the area of jurisdiction of the said five courts by a public order. If required by the High Court, the State Government may sanction extra strength of officers with requisite nfrastructure so that normal work of courts is not disturbed on account of the special arrangement for these cases.
(5) The officers posted will deal with these cases exclusively. If free from their work, any other work may be assigned to the said officers.
(6) The concerned authorities will be at liberty to encash the bank guarantee(s) after holding that there is a breach of terms of the agreement which decision will be subject to appropriate remedies of the parties.
(7) If not otherwise encashed, the bank guarantee will be kept alive till the trial is over. However, deposits/furnishing of bank guarantees will be abide by further orders of the trial court, interim or final.
(8) If any amount is deposited by the accused, the said amount will be adjusted in the amount of the bank guarantee, which is to be furnished by the accused.
(9) The accused will surrender their passports to the respective courts within a period of four weeks from today and will not leave the country without prior permission from the concerned court.

उक्त आदेश की कंडिका-1 का अनुपालन (एक महीने के अन्दर बैंक गारण्टी जमा करना) प्रमादी मिलरों द्वारा नहीं किया गया है। उक्त आदेश की कंडिका- 4 का अनुपालन (एक सप्ताह के अन्दर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पाँच जगहों- पटना, गया, छपरा, दरभंगा एवं पूर्णियाँ में विशेष ट्रायल कोर्ट का गठन) नहीं हो पाया है।

लगातार.....

अतएव विषय की महत्ता को देखते हुए अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में विधि विभाग, बिहार सरकार से माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पाँच जगहों– पटना, गया, छपरा, दरभंगा एवं पूर्णियाँ में विशेष ट्रायल कोर्ट का एक सप्ताह के अन्दर गठन करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(पंकज कुमार)
प्रबंध निदेशक।